अंतरिम बजट 2024-25: वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकलुभावन घोषणाएं नहीं कीं, दस वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं

खुद पर भरोसे का बजट

■ सौरभ शुक्ल

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। उनके बजट भाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसे की झलक साफ दिखी। वित्तमंत्री ने कोई लोकलुभावन घोषणाएं तो नहीं की, लेकिन बीते 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख जरूर किया। साथ ही उन्होंने आगामी वर्षों में सुधारों को आगे बढ़ाने का रोडमैप पेश किया।

सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, सरकार जुलाई में अपने बजट में भारत को विकसित देश बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश करेगी। उन्होंने बताया कि 'सुधार, प्रदर्शन और बदलाव' के सिद्धांत के आधार पर सरकार अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाएगी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ आम सहमति बनाएगी।

लंबी अवधि के विकास पर जोर: वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट में चुनिंदा क्षेत्रों को राहत देने का काम किया। इन ऐलानों से उनका जोर लंबी अवधि के विकास पर ही रहा है।

स्टार्ट अप को कर छूट के संकेत: सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने का ऐलान किया। सोलर पैनल लगाने पर इंसेंटिव का प्रावधान होगा। मध्यम वर्ग को घर देने के अलावा स्टार्टअप पर भी टैक्स छूट मिलेगी, इस बात के भी संकेत बजट से मिलते हैं।

कर विवादों पर राहत का प्रस्ताव: वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भले राहत नहीं दी, लेकिन 2009-10 तक के 25 हजार और वित्तवर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के 10 हजार की छोटी राशि की पुरानी कर मांग से जुड़े विवादों से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया।

हर चुनौती दूर की: एक घंटे से कम समय के भाषण में सीतारमण ने 10 वर्षों में सरकार की उन उपलब्धियों को रखा, जिससे देश 'नाजुक अर्थव्यवस्था' की श्रेणी से निकलकर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने कहा, 2014 से पहले की हर चुनौती को आर्थिक प्रबंधन और बेहतर राजकाज से दूर किया जा चुका है।

अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट दो हजार करोड़ रुपये बढ़ा

अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में दो हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अंतरिक्ष विभाग को 13,042.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 11,070.07 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए 10,087 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा विभाग के बजट में कटौती की गई है।

बिहार और झारखंड के विकास पर खास ध्यान

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार का फोकस हमेशा से गरीब, किसान, नारी और युवा पर रहा है। बजट भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाने वाला है। उनके मुताबिक देश में अगले दौर के आर्थिक सुधार पूर्वी हिस्से से होकर गुजरेंगे। आर्थिक योजनाओं को लागू करने का काम किया जाएगा। उन्होंने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नाम लेते हुए इन राज्यों की तरफ खास ध्यान दिए जाने की बात कही।

पूंजीगत व्यय 11% बढ़ाने का प्रस्ताव: सीतारमण ने 2024-25 का लेखानुदान पेश करते हुए बताया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को और गति देने के लिए पूंजीगत व्यय 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कर रही है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर इसे जीडीपी का 5.8% कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में यह 5.1% रहने का अनुमान है।

बजट विशेष P02,3,4,5,6,7,8

47.66 लाख करोड़ व्यय का बजट पेश किया गया

30.03 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान

- सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 5.1 फीसदी पर लाने का लक्ष्य रखा
- जुलाई के बजट में विकसित देश के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश करने का इरादा जताया

सरकार श्वेत पत्र लाएगी

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, सरकार वर्ष 2014 से पहले की आर्थिक स्थिति के बारे में श्वेत पत्र लाएगी। इससे ये पता चल सकेगा कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इसे अगले सप्ताह संसद में रखा जा सकता है।

रक्षा बजट में बढ़ोतरी

अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पिछले साल यह आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपये था। इसके साथ ही सरकार ने सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।

शेयर बाजार में मामूली गिरावट

शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुए। घरेलू बाजार अंतरिम बजट पेश किए जाते समय अस्थिर हो गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 106.81 अंक यानी 0.15 प्रतिशत गिरकर 71,645.30 अंक पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी 28.25 अंक यानी 0.13 प्रतिशत गिरकर 21,697.45 अंक पर आ गया।

> अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद।
>
> योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

> अंतरिम बजट केवल रंग-बिरंगे शब्दों का मायाजाल था। बड़े-बड़े और खोखले दावे करना सरकार की आदत है। बजट में पिछले वर्ष का ब्योरा और आने वाले साल का खाका होता है, पर इस बजट में दोनों में से कुछ भी नहीं है।
>
> मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

गरीब
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अंतरिम बजट में 20.5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

युवा
तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा, इससे शोधकर्ताओं को 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।

अन्नदाता
फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनेगी।

नारी
आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी आएंगी। वहीं, केंद्र सरकार ने बजट में 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का फैसला किया है।

'ज्ञान' का मंत्र: पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में विकसित भारत के लिए 'ज्ञान' का मंत्र दिया था। इसमें जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी सशक्तीकरण पर ध्यान देने को कहा था। बजट में इसका ध्यान रखा गया।

प्रमुख पांच

1 आयकर दरों में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी की गई है।

2 सेहत पर जोर
मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का इस्तेमाल कर सरकार अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी। इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

3 मुफ्त बिजली
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल के जरिये एक करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे सालाना हर परिवार के 18 हजार रुपये तक बचेंगे।

4 दो करोड़ घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पांच वर्षों में दो करोड़ घर बनाए जाएंगे। झुग्गी, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को घर खरीदने में मदद के लिए योजना लाई जाएगी।

5 नए रेल गलियारे
तीन आर्थिक रेल गलियारे बनेंगे। इनमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट, बंदरगाह संपर्क और यातायात गलियारा शामिल हैं। 40 हजार बोगियां वंदे भारत के तहत अपग्रेड की जाएंगी।